एजुकेशन प्री-समिट में हुए 28 हजार करोड़ के 507 एम.ओ.यू. : भजनलाल शर्मा

एजुकेशन प्री समिट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, कौशल नियोजन उद्यमिता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे।

- उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यिमता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा आयोजन
- नए शैक्षिक दृष्टिकोण, डिजिटल लर्निंग और रोजगारोन्मुखी कौशल एजुकेशन के साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश पर होगा गहन मंथन

जयपुर। कभी मरूभूमि के रूप में पहचान रखने वाला हमारा राजस्थान निरंतर प्रगति, समृद्धि और उन्नित के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास और जनता के हितोतार्थ राइजिंग राजस्थान जैसा ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व आयोजन आयोजित होने जा रहा है। इससे पूर्व प्रदेश की शिक्षा में नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त करने, सकारात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न उद्देश्यों को साकार करने और शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की दिशा में 6 नवंबर को होटल इंटरकॉन्टिनेंटल, टोंक रोड, जयपुर में एजुकेशन प्री-समिट 2024 का आयोजन किया गया। उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल एवं उद्यिमता विभाग तथा खेल एवं युवा मामलात के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित यह सम्मेलन न केवल शिक्षा क्षेत्र के भामाशाह, दानदाता, और हितधारकों को एक साथ लाएगा, बल्कि शिक्षा के भविष्य के विकास हेतु रणनीतियों और नवाचारों पर विचार-विमर्श का एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, कौशल नियोजन उद्यिमता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद रहे।

मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा विकास का मुख्य आधार होती है, शिक्षा में किया गया छोटा निवेश भी बड़ा प्रभाव लाता है। वह सबसे अहम होता है। उन्होने बताया कि प्री-समिट में 28 हजार करोड़ के 507 एमओयू किए गए हैं, जो शिक्षा, तकनीकी-उच्च शिक्षा, कौशल विकास व खेल में विकास की नई राह खोलेंगे। राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और हालांकि हमारे पास तैयारी के लिए सीमित समय था, लेकिन हम आपके सहयोग से इन पहलों को सफलतापूर्वक लागू करने में सक्षम होंगे। हम 6 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। चाहे खनन हो, स्वास्थ्य हो या ऊर्जा, सभी क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजस्थान के लिए आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत करेगा।" मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कुशल नेतृत्व में हो रही इस प्री समिट का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल, ई-लर्निंग, डिजिटल शिक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नए शैक्षिक दृष्टिकोण, कौशल विकास की सहायता से शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के प्रयास, नवाचार और भविष्य की संभावनाओं के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर उच्च-स्तरीय मंथन करना है। यह समिट राज्य की राजकीय शिक्षा में सुधार और उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके बाद शिक्षा में नवनिर्माण का नया युग प्रारंभ होना सुनिश्चित किया जाने की उम्मीद है।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। मुझे खुशी है कि इस आयोजन का उद्देश्य आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है।

शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अपनी माटी से जुड़ने के लिए मैं राजस्थान के लोगों का, निवेशकों, भामाशाहों, दानदाताओं का आभार प्रकट करता हूं। शिक्षा जीवन की नींव होती है, जो भी मंजिलें तय की जाएंगी, यह उनका आधार होगी। हम शिक्षा के साथ संस्कार देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कौशल नियोजन उद्यिमता विभाग, युवा एवं खेल विभाग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि शिक्षा डिग्री के लिए नहीं जीवन के लिए होनी चाहिए। खेल अनुशासन, आत्मविश्वास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजस्थान सरकार का ध्येय है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। इन उद्देश्यों की परिपूर्णता हेतु इस वृहत आयोजन में शिक्षा क्षेत्र के विशिष्ट नीति विशेषज्ञ, शिक्षाविद, उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां, भामाशाह, दानदाता और प्रदेश की शिक्षा को नई दिशा देने वाले विशेषजन शामिल हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भविष्य का राजस्थान विजन को साकार करने के तीव्र प्रयास राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। एजुकेशन प्री-समिट इसी स्वर्णीम यात्रा का एक अहम पड़ाव है। इस पड़ाव में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा , कैबिनेट मिनिस्टर कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ , उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित निवेशक एवं अधिकारी मौजूद रहे।

देवली-उनियारा, झुंझुनूं और खींवसर में त्रिकोणीय संघर्ष

बिगड़ रहे पार्टियों के समीकरण

- नरेश मीणा और राजेंद्र गुढ़ा ने कांग्रेस का संकट बढ़ाया, खींवसर में हनुमान बेनीवाल की कड़ी परीक्षा
- दौसा में पायलट, मुरारी और किरोड़ी की प्रतिष्ठा का चुनाव, सलूंबर में भाजपा तो रामगढ़ में कांग्रेस सहानुभूति के सहारे

जयपुर। राजस्थान में हो रहे उपचुनाव में देवली और दौसा के अलावा झुंझुनू और खींवसर विधानसभा सीट के उपचुनाव में सबसे ज्यादा रोमांच पैदा हुआ है। दरअसल इन सीटों पर बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा तो दाव पर लगी ही है। साथ ही इन सीटों के त्रिकोणीय मुकाबले ने भी चुनाव को काफी रोचक बना दिया है और यही कारण है कि रामगढ़, सलूंबर और चौरासी की जितनी चर्चा नहीं हो रही, उतनी इन चार सीटों की चर्चा हो रही है। सलूंबर में भाजपा और रामगढ़ में कांग्रेस सहानुभूति के आधार पर अपनी जीत के दावे कर रही है। वही चौरासी में बाप अपनी परंपरागत सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। वैसे उपचुनाव के परिणाम कुछ भी हो लेकिन यह तय है कि कांग्रेस के लिए यह उपचुनाव घाटे का सौदा साबित होंगे।

जहां तक सबसे रोमांचक मुकाबले की बात करें, तो वह देवली उनियारा में नजर आ रहा है, जहां कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय के तौर पर ताल ठोकने वाले नरेश मीणा ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। वहीं भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र गुर्जर को भी कड़ा प्रयास करना पड़ रहा है। दरअसल नरेश मीणा के साथ में युवाओं की भारी भीड़ जुटने की वजह से दोनों पार्टियां परेशानी में है और नरेश मीणा ने बिना किसी बड़े नेता के साथ हुए बिना भी देवली उनियारा में अपना प्रभाव दिखा रहे है। वहीं भाजपा से कांग्रेस में आए बिना ही के सी मीणा को टिकट दिए जाने पर स्थानीय कांग्रेसजन उम्मीदवार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इधर खींवसर सीट पर इस बार हनुमान बेनीवाल की कड़ी परीक्षा हो रही है। जहां उन्होंने अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को आरएलपी का उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने एक बार फिर रेवंत राम डागा को मौका दिया है, जो 2023 का चुनाव 2000 वोटो से हारे थे। वहीं कांग्रेस ने भी गठबंधन टूटने के बाद रतन चौधरी को मैदान में उतारा है। ऐसे में यहां त्रिकोणीय मुकाबले में एक-एक वोट का महत्व बढ़ गया है और सिर्फ हनुमान बेनीवाल नहीं, बल्कि पूरी आरएलपी पार्टी की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है।

जहां तक दौसा की बात करें, तो यहां डॉ किरोडी लाल मीणा के भाई जगमोहन भाजपा के उम्मीदवार है। ऐसे में यहां पूरा चुनाव डॉ किरोडी लाल मीणा के कंधे पर है। दूसरी ओर कांग्रेस में उम्मीदवार डीसी बैरवा के चलते सचिन पायलट और सांसद मुरारी लाल मीणा की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है। यहां जातीय समीकरण भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं और कुछ वोटो का इधर से उधर होना परिणाम को बदल सकता है। ऐसे में यहां का चुनाव भी काफी रोमांच भरा नजर आ रहा है। झुंझुनू में कांग्रेस में फिर ओला परिवार से उम्मीदवार आने से एक चर्चा चल पड़ी है कि क्या कांग्रेस ओला परिवार के बाहर भी निकलेगी। इस बात का कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। वहीं भाजपा ने एक बार फिर राजेंद्र भांभू पर विश्वास जताया है। साथ ही इस बार भाजपा में झुंझुनू में बगावत नहीं है। बबलू चौधरी का नामांकन वापस करवाकर भाजपा ने खुद को मुकाबले में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के लिए पूर्व मंत्री और निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र गुढ़ा ने परेशानी खड़ी कर दी है। मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों में राजेंद्र गुढ़ा की घुसपैठ कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होती लग रही है। यदि राजेंद्र गुढ़ा के साथ आ रही भीड़ वोटो में तब्दील हो गई, तो कांग्रेस को झुंझुनू में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

सी.एम. को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुर। जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-4 ने गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीएम भजनलाल शर्मा को मिली अग्रिम जमानत को रद्द कराने के लिए पेश प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। सांवरमल चौधरी ने अग्रिम जमानत की शर्त की अवहेलना कर अदालत की अनुमति के बिना विदेश जाने का आरोप लगाते हुए यह प्रार्थना पत्र पेश किया था।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रकरण में यह साबित नहीं है कि मामले में प्रार्थी का कोई हित जुड़ा हो या वह एफआईआर दर्ज कराने वाला हो। वह न तो मामले में पीड़ित है और ना ही उसे किसी प्रकार का नुकसान या उसका हित प्रभावित हुआ है। ऐसे में उसे प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि गोपालगढ़ दंगा प्रकरण में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर कई साल पहले आरोप पत्र पेश कर दिया है। इस एफआईआर में भजनलाल शर्मा ने अग्रिम जमानत के लिए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसे अदालत ने 10 सितंबर, 2013 को स्वीकार कर सशर्त अग्रिम जमानत दी थी। अग्रिम जमानत आदेश में शर्त लगाई गई थी कि भजनलाल बिना अदालत की अनुमति देश से बाहर नहीं जाएंगे। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भजनलाल शर्मा जमानत की शर्त की अवहेलना कर बिना अनुमति विदेश गए। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि भजनलाल अब प्रदेश के सीएम बन गए हैं और केन्द्र में भी भाजपा की सरकार है। अदालती आदेश की अवहेलना करने का तथ्य सामने लाने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की थी, लेकिन उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में अग्रिम जमानत को निरस्त कर उन्हें अभिरक्षा में लिया जाए। प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए सीएम की ओर से अधिवक्ता अश्विनी बोहरा ने कहा कि प्रार्थना पत्र दायर करने वाला निजी व्यक्ति है और उसके किसी अधिकार का हनन नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।

दिव्यांग को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने हिंदी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2023 से जुडे मामले में दिव्यांग याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश गिरिजेश व्यास की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने कॉलेज शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए गत वर्ष आवेदन मांगे थे। जिसमें याचिकाकर्ता ने दिव्यांग वर्ग की एलडी कैटेगरी में आवेदन किया। याचिकाकर्ता के पास बहु दिव्यांगता का प्रमाण पत्र है, जिसमें वह शरीर की दो दिव्यांगता से पीड़ित है।

मेडिकल कॉलेज की याचिका खारिज

- एमबीबीएस की सीटें कम करने को दी थी चुनौती

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आकस्मिक जांच में संसाधनों की कमियां पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज की एम.बी.बी.एस. की सीटें कम करने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसायटी, कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज, झालावाड की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के डीन ने अपील के निर्णय के दौरान सौ सीटों पर प्रवेश के साथ कॉलेज की स्थापना को स्वीकार किया था। ऐसे में याचिकाकर्ता एस्टोपल के सिद्धांत से बंधा हुआ है।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया था। इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद 24 मार्च, 2023 को पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को तीन शैक्षिणक सत्रों के लिए 150 सीटों की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति जारी कर दी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता और मान्यता के लिए आवेदन किया। आरयूएचएस ने भी 9 अप्रैल, 2023 को उसे अनुमति दे दी। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कॉलेज स्थापना के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के समक्ष अनुमति के लिए आवेदन किया। इस पर पर राष्ट्रीय चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड ने कुछ कमियां बताते हुए याचिकाकर्ता को गत तीन अप्रैल को नोटिस दिया। जिसका याचिकाकर्ता ने जवाब दे दिया। याचिका में कहा गया कि बोर्ड ने आकस्मिक निरीक्षण कर संस्थान में संसाधनों और फैकल्टी की कमी बताकर गत 4 जुलाई को 150 सीटों को घटाकर सौ सीटें कर दी।

माइंस विभाग का "राइजिंग राजस्थान" प्री-समिट 8 नवंबर को होगा

-कार्यालय संवाददाता-

प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बुधवार को खान विभाग के प्री समिट के आयोजन स्थल का निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल, जेएस आशु चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जायजा लिया।

- निवेश एम.ओ.यू. के साथ ही प्रदेश के माइनिंग क्षेत्र के समग्र विकास पर होगा मंथन
- राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक प्रदेश की खनिज संपदा थीम आधारित प्री-समिट
- खनन क्षेत्र के अब तक 70 हजार करोड़ से अधिक के एमओयू संपन्न
- समिट के दौरान प्रदर्शित होगी माइंस, पेट्रोलियम, सीजीडी गैस, रिफाइनरी से संबंधित ज्ञानवर्द्धक सामग्री

जयपुर। माइंस एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त बताया कि 8 नवंबर को जयपुर में आयोजित माइंस व पेट्रोलियम सेक्टर के प्री समिट में माइनिंग सेक्टर के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हस्ताक्षरित होने के साथ ही खनिज खोज और खनन से जुड़े हुए ज्वलंत विषयों पर इस क्षेत्र से जुड़े देश के जाने माने विशेषज्ञों के अनुभवों को साझा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आयोजन स्थल पर छह स्टॉलों में राजस्थान के माइंस, पेट्रोलियम, सीजीडी गैस और रिफाइनरी से संबंधित ज्ञानवर्द्धक सामग्री भी प्रदर्शित की जाएगी। प्री समिट राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रेरक प्रदेश की खनिज संपदा थीम पर आधारित होगा।

प्रमुख सचिव खान टी. रविकान्त ने बुधवार को आयोजन स्थल होटल ललित का निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल, जेएस आशु चौधरी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि माइनिंग एवं पेट्रोलियम सेक्टर में रोड शो व अन्य आयोजनों में अब तक 70 हजार करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 8 नवंबर को आयोजित प्री समिट में भी बड़ी संख्या में एमओयू हस्ताक्षरित होंगे।

टी. रविकान्त ने बताया कि माइनिंग सेक्टर के प्री समिट को अधिक उपयोगी व निवेशोन्मुखी बनाया जा रहा है। इस अवसर पर खनिज अन्वेषण, डाटा विष्लेषण, मशीन लर्निंग में आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की भूमिका और मिनरल एक्सप्लोरेशन में जियो इंफोरमेटिक्स की भूमिका पर धनबाद और कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर एसएस राय का विशेषज्ञ व्यक्तव्य और पर चर्चा होगी। इसी तरह से एक अन्य सत्र में डीप सीटेड बेस मेटल डिपोजिट्स लेड, जिंक, तांबा और संबंधित खनिजों पर अनिंध्य भट्टाचार्य उप महानिदेशक जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विशेषज्ञ व्यक्तव्य देंगे और उस पर चर्चा होगी।

क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट और प्लेटिनम गुरप ऑफ एलिमेंट्स पर चर्चा का एक सत्र रखा गया है जिसमें सीएमडी इंडियन रेयर अर्थ डॉ. दीपेन्द्र सिंह, रिटायर्ड प्रोफेसर एमके पण्डित, शैलेन्द्र शर्मा क्षेत्रीय निदेशक एएमडी, जीएसआई से संजय सिंह, एनपीईए के निदेशक डॉ. येरी स्वामी पाटिल पेनलिस्ट होंगे तो इस सत्र को निदेशक जीएसआई हरीश मिस्त्री मॉडरेट करेंगे। इसी तरह से खनिज संसाधन वृद्धि में खनन कंपनियोंऔर निजी अन्वेषण संस्थाओं की भूमिका पर मंथन होगा। इस सत्र में सीएमडी एचसीएल घनश्याम शर्मा, एनपीईए के निदेशक डॉ. चेन्नामल्लिकार्जुन बी पाटिल, हिन्दुस्तान जिंक के निदेशक एक्सप्लोरेशन कुलदीप सिंह सौलंकी, माइनिंग टेक्निकल इजिप्ट के प्रमुख मुस्तफा साबेर पेनलिस्ट होंगे और एसके मिण्डा मॉडरेटर होंगे।

प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि समिट में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को राजस्थान के खनिज व खनिज से जुड़ी जानकारियों से रुबरु कराने के लिए छह स्टॉल्स लगाई जाएगी। इनमें प्रदेश की खनिज, पेट्रोलियम, सीजीडी आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेष करते हुए खान विभाग, राजस्थान माइंस एवं मिनरल्स लि. आरएसएमएम, सीडॉस, एचआरआरएल राजस्थान रिफाइनरी, राजस्थान स्टेट गैस लि. व राजस्थान पेट्रोलियम की स्टॉल्स में ज्ञानवर्द्धक सामग्री प्रदर्शित की जाएगी।

निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान प्री समिट की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने प्रभारी अधिकारियों से प्रगति की जानकारी भी ली।

इस अवसर पर नोडल अधिकारी बीएस सोढ़ा, अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम अजय शर्मा, एमडी आरएसजीएल रणवीर सिंह, एसएमई जय गुरुबख्सानी, एनएस शक्तावत, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी संजय दुबे, संजय सक्सैना, डीजीएम आरएसजीएल विवेक श्रीवास्तव, डीएम आईटी गगनदीप राजोरिया सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।